शुक्रवार
21 अगस्त 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 209
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94 email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

गुलदार और भालू के बाद 'नई आफत'

पहाड़ों में खूंखार आवारा कुत्तों का कहर

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। पहाड़ में वन्यजीवों के बाद अब आवारा और हिंसक कुत्तों का आतंक भी लोगों के लिए चिंता का सबब बनता जा रहा है। चमोली जिले के नारायणबगड़ क्षेत्र में आवारा और हिंसक कुत्तों के बढ़ते आतंक को देखते हुए प्रशासन ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के मद्देनजर बड़ा फैसला लिया है। क्षेत्र के दस विद्यालयों में 20 अगस्त से 23 अगस्त तक छात्र-छात्राओं के लिए अवकाश घोषित कर दिया गया है। इस दौरान विद्यालयों में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाई जारी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

◆चमोली के नारायणबगड़ में हिंसक कुत्तों के डर से 10 स्कूलों में 4 दिन का अवकाश घोषित

◆स्कूल बंद होने के चलते अब घर बैठे आनलाइन माध्यम से पढ़ाई करने को मजबूर छात्र

◆मीलों पैदल सफर तय कर स्कूल जाने वाले नौनिहालों व अभिभावकों की उड़ी रातों की नींद

वन्यजीवों के बाद आवारा कुत्तों का संकट

उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष लंबे समय से गंभीर समस्या बना हुआ है। पहाड़ के गांवों में बाघ, गुलदार और भालू की आवाजाही से ग्रामीणों में भय बना रहता है। अब कई क्षेत्रों में आवारा और हिंसक कुत्तों के झुंड भी लोगों की सुरक्षा के लिए चुनौती बन रहे हैं। नारायणबगड़ का ताजा मामला इस बात का संकेत है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मानव सुरक्षा का संकट केवल जंगल से आने वाले वन्यजीवों तक सीमित नहीं रह गया है। सड़कों, बाजारों और आबादी के आसपास घूमने वाले आवारा कुत्ते भी प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बन चुके हैं।

पहाड़ के दूरदराज इलाकों में बच्चों का स्कूल तक पहुंचना पहले ही किसी चुनौती से कम नहीं है। कई बच्चे पैदल रास्तों से होकर विद्यालय पहुंचते हैं। ऐसे में रास्तों में हिंसक कुत्तों के झुंड का खतरा बच्चों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा रहा है। प्रशासन को बच्चों की सुरक्षा के लिए स्कूल बंद करने जैसा कदम उठाना पड़ा, यह स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कभी बाघ और गुलदार की दस्तक, कभी भालू का आतंक और अब आवारा कुत्तों के झुंड ग्रामीण आबादी के सामने नई चुनौती बनते जा रहे हैं। सवाल यह है कि जिन पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों को रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल पहुंचना पड़ता है, वहां उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसकी है?

नारायणबगड़ क्षेत्र में आवारा और हिंसक कुत्तों के आतंक को लेकर जिलाधिकारी चमोली की ओर से दिए गए निर्देशों के बाद मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय ने विद्यालयों के लिए आदेश जारी किया। आदेश में संबंधित विकासखंड शिक्षा अधिकारी और उप शिक्षा अधिकारी को इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही अवकाश की अवधि में संबंधित विद्यालयों के शिक्षकों को आनलाइन माध्यम से शिक्षण कार्य संचालित करने को कहा गया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह प्रभावित न हो।इस संबंध में मुख्य शिक्षा अधिकारी, चमोली की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नारायणबगड़ क्षेत्र में आवारा और हिंसक कुत्तों के अत्यधिक आतंक को देखते हुए जिलाधिकारी चमोली के निर्देशों के अनुपालन में छात्र-छात्राओं की सुरक्षा के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है।

आदेश के मुताबिक नारायणबगड़ क्षेत्र के राजकीय इंटर कालेज नारायणबगड़, राजकीय बालिका इंटर कालेज नारायणबगड़, सरस्वती शिशु मंदिर नारायणबगड़, उत्तरांचल विद्या निकेतन नारायणबगड़, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नारायणबगड़, श्री गुरु राम राय पब्लिक स्कूल पैंती, राजकीय प्राथमिक विद्यालय नलंगाव, राजकीय इंटर कालेज नलंगाव, माडर्न चिल्ड्रन एकेडमी नारायणबगड़ और उत्तराखंड विद्या निकेतन नारायणबगड़ में यह आदेश लागू रहेगा।

कांग्रेस विधायक को मिली जान से मारने की धमकी!

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। मंगलौर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन को अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप के माध्यम से आपत्तिजनक सामग्री भेजने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी है। विधायक की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मंगलौर विधानसभा क्षेत्र के विधायक काजी मोहम्मद निजामुद्दीन ने पुलिस को दी गई तहरीर में बताया कि उनके व्हाट्सएप अकाउंट पर दो अलग-अलग मोबाइल नंबरों से आपत्तिजनक सामग्री भेजी गई। इनमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाले ऑडियो, वीडियो और संदेश शामिल थे। इन संदेशों में विधायक की धार्मिक पहचान को निशाना बनाते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। सबसे गंभीर बात यह रही कि भेजी गई सामग्री में एक नकाबपोश व्यक्ति का वीडियो भी शामिल था। इस वीडियो में नकाबपोश व्यक्ति साफ-साफ विधायक को जान से मारने की धमकी दे रहा था। विधायक ने इसे गंभीर सुरक्षा खतरा बताते हुए पुलिस से तुरंत कार्रवाई की मांग की।

पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि विधायक की तहरीर के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिन मोबाइल नंबरों से धमकी भरे संदेश और आपत्तिजनक सामग्री भेजी गई, उन्हें ट्रेस करने का काम तेजी से चल रहा है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी की पहचान कर धरपकड़ की जाएगी। वहीं कांग्रेस विधायक को धमकी देने के मामले के बाद राजनीतिक हल्कों में भी हलचल मच गयी है। फिलहाल मंगलौर विधायक का इस मामले में कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

दून वैली मेल

संपादकीय

महंगाई की चाशनी में आमजन

चीनी की कीमत बढ़ना सिर्फ बाजार की एक खबर नहीं है। यह उस रसोई की कहानी है जहां हर महीने आमदनी और खर्च के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है। सरकार चाहे महंगाई के आंकड़े कितने ही संतोषजनक क्यों न बताए, लेकिन बाजार में खड़ा उपभोक्ता आंकड़ों से नहीं, कीमतों से अपना घर चलाता है। और जब चीनी जैसी रोजमर्रा की जरूरत की चीज महंगी होती है तो सवाल सिर्फ कुछ रुपये का नहीं, सरकार की आर्थिक प्राथमिकताओं का होता है। महंगाई का सबसे खतरनाक रूप वही है जो धीरे-धीरे सामान्य बना दिया जाए। पहले तेल महंगा हुआ, फिर सब्जियां, दालें और दूसरी खाद्य वस्तुएं महंगी हुईं। अब चीनी की बढ़ती कीमतें बताती हैं कि आम आदमी की रसोई पर दबाव कम नहीं हुआ है। हर बार सरकार के पास कारणों की लंबी सूची होती है उत्पादन, मौसम, मांग, आपूर्ति, परिवहन, वैश्विक बाजार। लेकिन उपभोक्ता के पास सिर्फ एक सवाल हैकृमेरी जेब पर बोझ कम कब होगा? चीनी के मामले में स्थिति और भी दिलचस्प है। खेत में गन्ना पैदा करने वाला किसान अपनी लागत और मेहनत का उचित मूल्य मांगता है। चीनी मिलें अपनी लागत और आर्थिक दबाव का हवाला देती हैं। बाजार में व्यापारी अपनी मजबूरियां गिनाता है। लेकिन इस पूरी श्रृंखला का अंतिम सिरा हमेशा उपभोक्ता ही क्यों बनता है? सरकार को यह जवाब देना होगा कि कीमतों के इस खेल में निगरानी की व्यवस्था कहां है। यदि उत्पादन पर्याप्त है तो कीमत क्यों बढ़ रही है? यदि स्टाक मौजूद है तो बाजार में महंगाई क्यों है? यदि जमाखोरी नहीं है तो उपभोक्ता को राहत क्यों नहीं मिल रही? और यदि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां जिम्मेदार हैं तो सरकार के पास उपभोक्ताओं को राहत देने की क्या रणनीति है? यह भी समझना होगा कि चीनी अकेली चीज नहीं है। इसकी कीमत बढ़ने का असर चाय, मिठाई, बेकरी और अनेक खाद्य उत्पादों पर पड़ता है। यानी एक वस्तु की कीमत बढ़ने से महंगाई का असर कई दूसरी वस्तुओं तक पहुंच जाता है। सबसे ज्यादा चोट गरीब और निम्न-मध्यम वर्ग को लगती है, जिसके पास बढ़ते खर्च के मुकाबले आय बढ़ाने के विकल्प सीमित हैं। विडंबना यह है कि राजनीतिक मंचों पर आम आदमी की जिंदगी आसान बनाने के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। लेकिन असली परीक्षा मंच पर नहीं, रसोई में होती है। वहां जनता पूछती है कि महीने के आखिरी सप्ताह में राशन क्यों कम पड़ जाता है? बच्चों की जरूरतों और घर के खर्च के बीच संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? और रोजमर्रा की वस्तुओं की कीमतों पर सरकार की पकड़ आखिर कितनी है? महंगाई को सिर्फ बाजार की समस्या मानकर सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। सरकार की जिम्मेदारी है कि वह उत्पादन से लेकर वितरण तक पूरी श्रृंखला पर निगरानी रखे, जमाखोरी और कृत्रिम कमी के खिलाफ कार्रवाई करे और किसान तथा उपभोक्ता दोनों के हितों के बीच संतुलन बनाए। क्योंकि किसान को उचित दाम और उपभोक्ता को उचित कीमत दोनों एक साथ संभव हैं। समस्या तब पैदा होती है जब नीति का फायदा किसी और को मिले और कीमत जनता चुकाए। चीनी की कीमतों का मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि यह सरकार के लिए एक चेतावनी है। महंगाई को आंकड़ों से नहीं, जनता की थाली और रसोई से मापा जाना चाहिए। यदि आम आदमी की खरीदने की क्षमता लगातार कमजोर हो रही है तो आर्थिक विकास के बड़े-बड़े दावे उसके लिए अधूरे हैं। देश को ऐसी अर्थव्यवस्था नहीं चाहिए जिसमें सरकार उपलब्धियों की मिठास का प्रचार करे और जनता महंगाई की कड़वाहट चखे। चीनी महंगी होने का सवाल छोटा हो सकता है, लेकिन इसके पीछे छिपा सवाल बहुत बड़ा है आखिर आर्थिक नीतियों का केंद्र कौन है जनता या बाजार? सरकार को इसका जवाब आंकड़ों में नहीं, राहत देकर देना होगा।

नौकरी दिलाने के नाम पर की 18 लाख की ठगी, गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

पौड़ी। नौकरी दिलाने के नाम पर 18 लाख रूपये की ठगी करने वाले एक शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार ठिकाने बदल रहा था। जानकारी के अनुसार सूर्यकान्त बलूनी,निवासी जौनपुर कोटद्वार द्वारा कोतवाली कोटद्वार पर तहरीर देकर बताया गाय था कि प्रदीप सैनी निवासी हरिद्वार द्वारा नौकरी लगाने के नाम पर उनसे 18 लाख रुपये लिये गये है और उसके द्वारा न तो नौकरी दिलाई गई और न ही पैसे वापस किये जा रहे है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गयी। जांच के क्रम में आरोपी को सहयोग हेतु उपस्थित होने के लिए कई बार नोटिस एवं सूचना दी गई, किन्तु वह पुलिस के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ। इसके उपरांत आरोपी की गिरफ्तारी हेतु उसके संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई, परंतु वह अपने निवास स्थान एवं अन्य संभावित स्थानों से लगातार फरार रहा। गिरफ्तारी से बचने के उद्देश्य से लगातार अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा आरोपी के खिलाफ गैर-जमानती वारंट (एनबीडब्लू) जारी किया गया। जिसके बाद पुलिस ने उसे बीती रात एक सूचना के बाद आरोपी प्रदीप सैनी पुत्र महेन्द्र सिंह सैनी निवासी शिवालिक नगर हरिद्वार से गिरफ्तार कर लिया गया है।

लोकतंत्र की पहली शर्त पर 'पालिटिकल वार'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। लोकतंत्र की सबसे पहली शर्त है कि मतदाता सूची साफ हो, सही हो और उसमें वही नाम हों जो वास्तव में मतदान के पात्र हैं। लेकिन उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासत लगातार गरमाती जा रही है। कांग्रेस इस प्रक्रिया पर सवाल उठा रही है, जबकि भाजपा इसे मतदाता सूची को शुद्ध करने की जरूरी कवायद बता रही है। सवाल अब यह उठ रहा है कि अगर एसआईआर का मकसद मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाना है तो कांग्रेस को इससे परेशानी क्यों हो रही है?

कांग्रेस का तर्क है कि पुनरीक्षण की प्रक्रिया में वास्तविक मतदाताओं के नाम कटने का खतरा है और किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। पार्टी लगातार मांग कर रही है कि प्रक्रिया पारदर्शी हो और प्रत्येक नाम हटाने से पहले उचित सत्यापन किया जाए। लेकिन भाजपा कांग्रेस के इस विरोध को राजनीतिक चश्मे से देख रही है। भाजपा नेताओं का सवाल है कि अगर मतदाता सूची में फर्जी, डुप्लीकेट या अपात्र नाम हैं तो उन्हें हटाने का विरोध क्यों? लोकतंत्र में मतदाता सूची जितनी साफ होगी, चुनाव उतने ही निष्पक्ष होंगे। यहीं से एसआईआर सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं

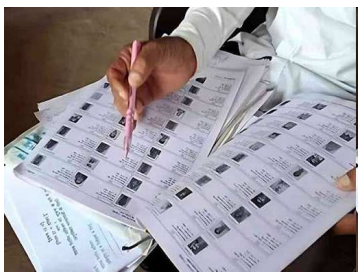

◆उत्तराखंड में मतदाता सूची पर बढ़ी रार, मतदाता सूची की शुद्धि पर गरमाई राजनीति
◆वास्तविक मतदाताओं के नाम कटने का खतरा, कांग्रेस ने सत्यापन की उठाई मांग
◆सूची की सफाई पर विरोध क्यों, भाजपा बोली फर्जी नामों को हटाना बेहद जरूरी

रह जाता, बल्कि राजनीतिक बहस का मुद्दा बन जाता है।

कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वह चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता की बात करती है तो उसे मतदाता सूची के शुद्धिकरण का सिद्धांतत: विरोध क्यों करना चाहिए? उसे यह स्पष्ट करना होगा कि वह एसआईआर के खिलाफ है या उस तरीके के खिलाफ जिसमें एसआईआर को लागू किया जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार और निर्वाचन तंत्र की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। सिर्फ यह कह देना पर्याप्त नहीं कि सूची शुद्ध की जा रही है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वास्तविक मतदाता का नाम गलती से न कटे। खासकर पहाड़ी और दूरदराज के इलाकों में जहां पलायन, अस्थायी निवास और दस्तावेजों से जुड़े सवाल पहले से जटिल हैं, वहां विशेष सावधानी की जरूरत है।

मतदाता सूची की शुचिता लोकतंत्र की बुनियाद है। इसमें फर्जी नाम नहीं होने चाहिए, लेकिन किसी वास्तविक नागरिक का नाम भी सिर्फ तकनीकी गलती से नहीं हटना चाहिए। कांग्रेस को बताना होगा कि उसे शुद्ध मतदाता सूची से परेशानी है या प्रक्रिया से और सरकार को बताना होगा कि वह शुद्धिकरण के नाम पर किसी वास्तविक मतदाता के अधिकार की रक्षा कैसे करेगी। आखिर चुनाव सिर्फ जीतने-हारने का खेल नहीं है। मतदाता सूची में दर्ज हर नाम लोकतंत्र में एक नागरिक की आवाज है। इसलिए एसआईआर पर राजनीति हो सकती है, लेकिन मतदाता के अधिकार से खिलवाड़ नहीं।

2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के बीच मतदाता सूची पर उठते सवालों को हल्के में लेना किसी भी दल के लिए राजनीतिक रूप से भारी पड़ सकता है। कांग्रेस हो या भाजपा दोनों को याद रखना होगा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा वोट बैंक कोई पार्टी नहीं, खुद मतदाता है।

आजादी के 'महामंत्र' पर राजनीति

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। जिस देश की आजादी की लड़ाई में वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं, बल्कि अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रतिरोध की आवाज बन गया था, उसी देश में इसके गायन को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा होना निश्चित तौर पर गंभीर सवाल पैदा करता है। कांग्रेस की ओर से कार्यक्रमों में वंदे मातरम के पूरे गायन को लेकर उठे सवालों ने भाजपा को कांग्रेस पर हमला करने का मौका दे दिया है। भाजपा इसे राष्ट्रभावना से जोड़कर कांग्रेस के खिलाफ राजनीतिक हथियार बना रही है, जबकि कांग्रेस की ओर से इसे राजनीतिक मुद्दा बनाए जाने पर सवाल उठाए जा रहे हैं।

आजादी के आंदोलन के दौर में वंदे मातरम ने लोगों के भीतर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम किया। स्वतंत्रता सेनानियों के नारों में यह गूंजता था और ब्रिटिश शासन के विरोध का प्रतीक बन चुका था। ऐसे में इस गीत को लेकर किसी भी तरह का विवाद भावनात्मक रूप से देश के बड़े वर्ग को प्रभावित करता है।

भाजपा का आरोप है कि कांग्रेस का रवैया राष्ट्रवादी प्रतीकों को लेकर हमेशा से दोहरा रहा है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जिस वंदे मातरम को स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष में अपनी आवाज बनाया, उसके गायन से कांग्रेस का पीछे हटना दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा इस मुद्दे को कांग्रेस की कथित तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़कर भी देख रही है। हालांकि इस पूरे विवाद का दूसरा पहलू भी है। वंदे मातरम के इतिहास, इसके विभिन्न पदों और स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका को समझे बिना इसे सिर्फ राजनीतिक नारे

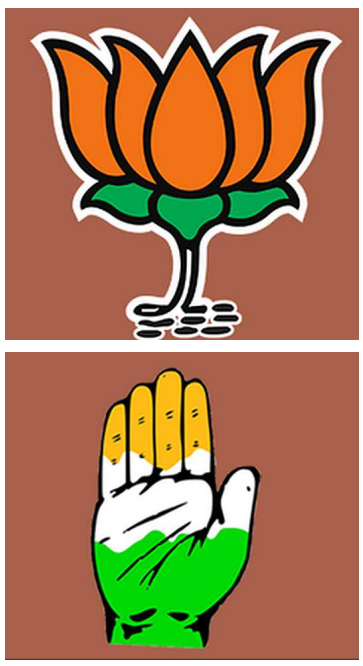

◆वंदे मातरम के गायन पर आमने-सामने भाजपा और कांग्रेस
◆पूरे गायन पर उठे सवाल और सियासत का बन गया नया केंद्र
◆भाजपा ने बनाया हथियार, कांग्रेस की मंशा पर उठाए सवाल

में बदल देना भी उचित नहीं होगा। राष्ट्रगीत का सम्मान और उसके राजनीतिक इस्तेमाल के बीच अंतर बनाए रखना जरूरी है।

असल सवाल यह है कि क्या देशभक्ति का प्रमाण अब इस बात से तय होगा कि कौन कितना जोर से वंदे मातरम गाता है? अगर कोई दल या नेता इसके गायन को लेकर सवाल उठाता है तो उससे सवाल जरूर होना चाहिए। लेकिन इसी के साथ यह भी पूछा जाना चाहिए कि आजादी के आंदोलन के प्रतीकों का इस्तेमाल सिर्फ चुनावी राजनीति के लिए क्यों किया जा रहा है? वंदे मातरम् की ताकत उसकी धुन में नहीं, उस इतिहास में है जिसमें यह करोड़ों भारतीयों की आवाज बना था। इसलिए इसे राजनीतिक अखाड़े में खींचने के बजाय उसके ऐतिहासिक महत्व और राष्ट्रीय भावना का सम्मान किया जाना चाहिए।

कांग्रेस के लिए भी यह राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील मामला है। अगर उसके किसी कार्यक्रम में राष्ट्रगीत के गायन को लेकर असमंजस या अनिच्छा दिखाई देती है तो पार्टी को देश के सामने अपना पक्ष साफ करना चाहिए। उसे यह स्पष्ट करना होगा कि क्या वह वंदे मातरम के सम्मान और उसके गायन के खिलाफ है या केवल उसके राजनीतिक इस्तेमाल का विरोध कर रही है। क्योंकि जनता के लिए संदेश महत्वपूर्ण है। जिस गीत को स्वतंत्रता आंदोलन में देश की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे लोगों ने अपनी आवाज बनाया, उसके प्रति किसी भी राजनीतिक दल की असंवेदनशीलता सवालों के घेरे में आएगी।

लेकिन भाजपा को भी यह समझना होगा कि राष्ट्रभक्ति किसी एक राजनीतिक दल की निजी संपत्ति नहीं है। वंदे मातरम किसी पार्टी का गीत नहीं, देश के स्वतंत्रता संघर्ष की ऐतिहासिक विरासत है। इसलिए इसे लेकर राजनीति जितनी कम होगी, सम्मान उतना ही ज्यादा रहेगा। देश को आज भी वंदे मातरम की जरूरत है लेकिन राजनीतिक हथियार के रूप में नहीं, उस साझा राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक के रूप में जिसने कभी अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती देने का साहस दिया था।

वोट की चोट के नारों से सत्ता में 'खलबली'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून/नई दिल्ली। सियासत में नाराजगी कोई नई चीज नहीं है। लेकिन जब नाराजगी सवाल पूछने लगे, जब सवाल नारे बन जाएं और नारे चुनावी बातचीत का हिस्सा बनने लगें, तब सत्ता को ठहरकर सुनना पड़ता है। आज देश के कई हिस्सों में युवाओं के बीच कुछ ऐसा ही माहौल दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी और पेपर लीक जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। कहीं युवा कह रहे हैं गलती से भी वोट नहीं देंगे। कहीं सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं और कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए युवाओं का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है।

इस गुस्से को समझने के लिए सिर्फ राजनीतिक भाषण सुनना काफी नहीं होगा। उस युवा को सुनना होगा जो वर्षों से परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वह परिवार सुनना होगा जिसने कोचिंग और रहने पर पैसा खर्च किया। वह अभ्यर्थी सुनना होगा जिसकी परीक्षा रद्द हो गई या जिसकी मेहनत पर प्रश्नपत्र लीक होने की खबर ने पानी फेर दिया। यही वह जगह है जहां पेपर लीक की राजनीति, बेरोजगारी की चिंता और चुनावी नाराजगी एक-दूसरे से जुड़ती दिखाई देती है।

प्रधानमंत्री मोदी की ओर से राजनीतिक विरोधियों पर किए गए तीखे तंजों के बीच विपक्ष और सोशल मीडिया ने भी अपनी शब्दावली गढ़ ली है। काकरोच जनता पार्टी जैसा व्यंग्य इसी राजनीतिक भाषा की नई अभिव्यक्ति है। नाम चाहे जो हो, असली सवाल नाम का नहीं है। सवाल यह है कि जनता किसे वोट देगी और क्यों देगी?

लोकतंत्र में चुनाव सिर्फ सरकार की उपलब्धियों का उत्सव नहीं होते। वह जनता की शिकायतों की सुनवाई भी होते हैं और जब युवा अपने अनुभवों को राजनीतिक सवाल में बदलने लगते हैं तो चुनावी समीकरणों में उसका असर पड़ना स्वाभाविक है। आज का युवा केवल यह नहीं पूछ रहा कि देश कितना आगे बढ़ा। वह यह भी पूछ रहा है कि मेरी नौकरी कहां है? मेरी परीक्षा सुरक्षित क्यों नहीं है? मेरी मेहनत की गारंटी कौन देगा? इन सवालों का जवाब किसी नारे से नहीं दिया जा सकता।

पेपर लीक की घटनाओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। परीक्षा की तैयारी करने वाला युवा सिर्फ किताब नहीं पढ़ता। वह अपनी उम्र के कई साल उस परीक्षा के नाम कर देता है। जब परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठता है तो नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का नहीं होता। नुकसान उस भरोसे का होता है जिसके आधार पर लाखों युवा अपने भविष्य की योजना बनाते हैं। यही वजह है कि पेपर लीक का मुद्दा अब विपक्ष के भाषणों से आगे निकलकर युवाओं की निजी जिंदगी का सवाल बन चुका है। सरकारें जांच की घोषणा कर सकती हैं। एजेंसियां जांच कर सकती हैं। गिरफ्तारियां हो सकती हैं। लेकिन जिस युवा ने दो-तीन साल तैयारी में लगाए, उसके समय का क्या? यही सवाल चुनावी राजनीति में सबसे ज्यादा असहज करने वाला हो सकता है।

भाजपा की ताकत उसका संगठन है। उसका बूथ नेटवर्क है। उसका चुनावी प्रबंधन है। उसके पास प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा राजनीतिक चेहरा है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा वर्ग भी है जिसे किसी राजनीतिक दल का स्थायी वोटर मान लेना खतरनाक होगाकृयुवा। यह युवा जाति, क्षेत्र और परंपरागत राजनीतिक पहचान से आगे जाकर रोजगार, परीक्षा, शिक्षा और अवसर की भाषा में सवाल पूछ रहा है। सोशल मीडिया ने इस गुस्से को और तेज कर दिया है। एक शहर में हुआ प्रदर्शन दूसरे शहर तक पहुंच जाता है। एक अभ्यर्थी का वीडियो हजारों युवाओं तक पहुंच जाता है। एक पेपर लीक की खबर देखते ही दूसरे राज्यों के युवा अपने अनुभव साझा करने लगते हैं। यानी पहले जिस नाराजगी को सत्ता स्थानीय घटना मानकर टाल सकती थी, वह अब कुछ ही घंटों में राष्ट्रीय राजनीतिक मुद्दा बन सकती है।

शहरों की सड़कों पर दिखाई दे रहा गुस्सा अगर गांवों और कस्बों तक पहुंच गया, और युवाओं की नाराजगी मतदान के फैसले में बदल गई, तो 2027 की राजनीति में यह सिर्फ विपक्ष की कहानी नहीं होगी यह सत्ता के लिए सबसे बड़ा सवाल बन सकती है और सवाल वही रहेगा कि जिस युवा ने नौकरी के लिए अपनी जवानी लगाई, अगर वह सरकार से कहे कि अब वोट सोच-समझकर देंगे, तो क्या सत्ता उसकी आवाज सुनेगी?

चुनावी साल में सबसे बड़ा सवाल

सियासत में अक्सर बड़े मुद्दों के बीच छोटे-छोटे सवाल दब जाते हैं। लेकिन कभी-कभी वही छोटे सवाल चुनाव का बड़ा मुद्दा बन जाते हैं। एक बेरोजगार युवक का सवाल। एक रद्द हुई परीक्षा का सवाल। एक पेपर लीक से टूटे भरोसे का सवाल। एक परिवार की आर्थिक चिंता का सवाल और फिर वह वाक्य गलती से भी वोट नहीं देंगे। यह वाक्य अपने आप में चुनाव का परिणाम नहीं बताता। लेकिन यह जरूर बताता है कि सत्ता के सामने सवाल खड़े हो चुके हैं। अब देखना यह है कि इन सवालों का जवाब भाषणों से दिया जाता है या नीतियों से। क्योंकि लोकतंत्र में जनता को हमेशा चुप नहीं कराया जा सकता। कभी-कभी जनता चुप रहती है, कभी सड़क पर आती है और कभी ईवीएम के सामने खड़ी होकर जवाब देती है।

◆सालों की मेहनत, कोचिंग का कर्ज और लगातार रद्द होती परीक्षाओं से सब्र का बांध टूटा
◆नारों में बदला बेरोजगारों का आक्रोश, 2027 के सियासी समीकरण बिगाड़ने का अल्टीमेटम
◆शहर-शहर मोदी के खिलाफ जनता का गुस्सा, युवाओं की नाराजगी बनी बड़ी चुनौती

वोट नहीं देंगे से किसे देंगे तक का सवाल

हालांकि चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। सरकार से नाराज होना और विपक्ष को वोट देनाकृदो अलग बातें हैं। अगर कोई युवा कहता है कि वह मौजूदा सरकार को वोट नहीं देगा, तो अगला सवाल होगा वह किसे वोट देगा?यही विपक्ष की असली परीक्षा है। सत्ता के खिलाफ गुस्सा पैदा करना आसान है। उस गुस्से को राजनीतिक विकल्प में बदलना कठिन है। युवाओं की नाराजगी को वोट में बदलने के लिए विपक्ष को सिर्फ मोदी विरोध से आगे जाना होगा। उसे रोजगार, परीक्षा सुधार, भर्ती कैलेंडर, पेपर लीक पर जवाबदेही और युवाओं के भविष्य का स्पष्ट रोडमैप देना होगा।वरना चुनाव के बाद यही गुस्सा फिर सोशल मीडिया पर लौट सकता है।

भाजपा का 'आपरेशन 2027' शुरू

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच भाजपा ने संगठन को चुनावी मोड में डालना शुरू कर दिया है। पार्टी ने प्रदेश के 19 सांगठनिक जिलों के लिए प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। पहली नजर में यह सामान्य संगठनात्मक फेरबदल दिखाई दे सकता है, लेकिन चुनावी राजनीति के लिहाज से देखें तो भाजपा का यह कदम काफी महत्वपूर्ण है। पार्टी ने जिलों में ऐसे समय पर जिम्मेदारियां तय की हैं, जब चुनावी मैदान तैयार हो रहा है और टिकट से लेकर बूथ प्रबंधन तक हर स्तर पर राजनीतिक समीकरण तेजी से आकार ले रहे हैं। भाजपा की राजनीति में संगठन केवल चुनाव के समय सक्रिय होने वाला ढांचा नहीं है। बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक लगातार सक्रिय रहने वाला कैडर उसका सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार माना जाता है। यही वजह है कि 19 सांगठनिक जिलों में प्रभारी और सह प्रभारियों की नियुक्ति को 2027 की चुनावी रणनीति की शुरुआती बड़ी कवायद के तौर पर देखा जा रहा है।

उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों का चुनाव केवल बड़े राजनीतिक नारों से नहीं जीता जाता। यहां पहाड़ और मैदान की अलग-अलग राजनीतिक जरूरतें हैं। कुमाऊं और गढ़वाल के भीतर भी क्षेत्रवार मुद्दे और जातीय-सामाजिक समीकरण अलग हैं। ऐसे में प्रदेश मुख्यालय से चुनावी रणनीति बनाने के बजाय उसे जिले और मंडल स्तर तक पहुंचाना भाजपा की प्राथमिकता होगी। नए प्रभारी और सह प्रभारी इसी काम की कड़ी होंगे। उनकी जिम्मेदारी केवल बैठकों तक सीमित नहीं रहेगी। संगठन की वास्तविक स्थिति, बूथ कमेटियों की सक्रियता, स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल, सरकार की योजनाओं का प्रचार और जनता के बीच पार्टी की पकड़ जैसे मुद्दों पर भी नजर रखनी होगी। यानी भाजपा चुनाव आने से पहले ही यह जान लेना चाहती है कि कौन सा बूथ मजबूत है, कहां संगठन कमजोर है और कहां पार्टी के भीतर ही असंतोष चुनावी नुकसान का कारण बन सकता है।

भाजपा के लिए 2027 का चुनाव केवल संगठन की परीक्षा नहीं है। प्रदेश की सरकार के कामकाज का भी जनमत संग्रह होगा। धामी सरकार डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल को चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश करेगी। लेकिन विपक्ष बेरोजगारी, पलायन, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, आपदा प्रबंधन और युवाओं से जुड़े सवालों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। ऐसे में जिला प्रभारियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्हें केवल पार्टी का पक्ष जनता तक पहुंचाना नहीं होगा, बल्कि जनता के सवालों और नाराजगी की रिपोर्ट भी ऊपर तक पहुंचानी होगी। क्योंकि चुनावी राजनीति में सबसे खतरनाक स्थिति वह होती है जब पार्टी के पास कागजों में मजबूत संगठन हो, लेकिन जमीन पर मतदाता उससे दूरी बनाने लगे।

2027 के चुनाव से पहले भाजपा के सामने एक और बड़ी चुनौती टिकट की

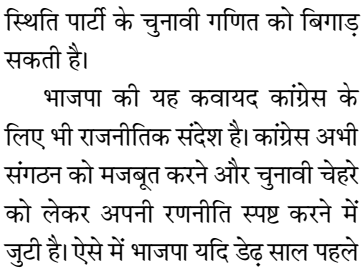

◆19 जिलों में भाजपा की नई तैनाती, चुनावी बिसात पर संगठन
◆प्रभारी-सह प्रभारियों की नियुक्ति महज संगठन विस्तार ही नहीं
◆विस चुनाव से पहले बूथ तक पकड़ मजबूत करने की कवायद

होगी। हर विधानसभा क्षेत्र में संभावित दावेदार सक्रिय हो चुके हैं। कई पुराने चेहरे टिकट की उम्मीद लगाए बैठे हैं, तो नए नेता भी संगठन में अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हैं। जिला प्रभारी और सह प्रभारी ऐसे समय में पार्टी के भीतर शक्ति संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें यह भी देखना होगा कि टिकट की होड़ संगठनात्मक गुटबाजी में न बदल जाए। क्योंकि भाजपा के लिए सबसे बड़ा खतरा विपक्ष से पहले अपनों की नाराजगी हो सकती है। टिकट कटने के बाद बगावत, भीतरघात या निर्दलीय मैदान में उतरने की स्थिति पार्टी के चुनावी गणित को बिगाड़ सकती है।

भाजपा की यह कवायद कांग्रेस के लिए भी राजनीतिक संदेश है। कांग्रेस अभी संगठन को मजबूत करने और चुनावी चेहरे को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट करने में जुटी है। ऐसे में भाजपा यदि डेढ़ साल पहले ही जिलेवार संगठन की जिम्मेदारी तय कर रही है तो इसका अर्थ साफ है पार्टी चुनाव को अंतिम छह महीने की लड़ाई नहीं मान रही। भाजपा चाहती है कि चुनाव की घोषणा होने से पहले ही उसका संगठन मतदाता तक पहुंच चुका हो। सरकार की उपलब्धियां बूथ तक पहुंचें, लाभार्थियों से संपर्क हो, स्थानीय मुद्दों की पहचान हो और कमजोर सीटों पर पहले से काम शुरू किया जाए।

हालांकि भाजपा की संगठनात्मक ताकत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन चुनाव केवल संगठन के दम पर नहीं जीते जाते। अंतत: मतदाता यह तय करता है कि सरकार ने उसके जीवन में कितना बदलाव किया। 19 जिलों में प्रभारी-सह प्रभारी नियुक्त करना भाजपा की तैयारी का संकेत जरूर है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि 2027 का चुनाव पार्टी के लिए आसान होगा। पहाड़ की नाराजगी, युवाओं के रोजगार के सवाल, सरकारी नौकरियों की भर्ती, पलायन, महिलाओं की सुरक्षा और महंगाई जैसे मुद्दे चुनावी हवा का रुख बदल सकते हैं। इसलिए भाजपा के सामने चुनौती सिर्फ संगठन खड़ा करने की नहीं, बल्कि संगठन को जनता की नब्ज पढ़ने वाली मशीन बनाने की है।

2027 की चुनावी बिसात पर भाजपा ने पहली बड़ी चाल चल दी है। अब देखना यह होगा कि जिला प्रभारी और सह प्रभारी पार्टी के लिए सिर्फ बैठकें और रिपोर्ट तैयार करते हैं या वास्तव में जमीन पर संगठन की कमजोर नसों को पकड़ पाते हैं। क्योंकि चुनाव बूथ पर लड़ा जाएगा, लेकिन उसका फैसला जनता के मन में होगा।

सितंबर तक विशेषज्ञ डॉक्टर नहीं मिले तो करेंगे आंदोलन

उत्तरकाशी(आरएनएस)। जिला अस्पताल में सर्जन और बाल रोग विशेषज्ञ की तैनाती के लिए कांग्रेस ने स्वास्थ्य विभाग को दो सितंबर तक डॉक्टरों की तैनाती की मांग की है। साथ ही ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।

कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने सीएमओ से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि जिला अस्पताल लंबे समय से विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी से जूझ रहा है। सर्जन और बाल रोग विशेषज्ञ के पद रिक्त होने से गंभीर मरीजों को उपचार के लिए देहरादून या अन्य जनपदों में रेफर करना पड़ रहा है।

कांग्रेस नेताओं ने कहा कि चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं पर दबाव और बढ़ जाता है। ऐसे में जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों के अभाव में स्थानीय स्तर पर उपचार की सुविधा प्रभावित होने के साथ मरीजों और उनके परिजनों को लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है।

जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह रावत ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ज्ञापन देने वालों में कनकपाल सिंह परमार, दिनेश गौड़, मनीष पंवार, जीतम सिंह रावत, सुधीश पंवार, भगवान चंद्र, रमन कठैत, संतोष भंडारी मौजूद रहे।

दिनभर कॉफी पीने की आदत आपकी रात की नींद को कर सकती है प्रभावित, जानिए कैस

सुबह के समय कई लोग एक कप कॉफी पी कर दिन शुरू करते हैं। यह न केवल आपको ऊर्जा देती है, बल्कि दिनभर ताजगी भी महसूस कराती है। हालांकि, क्या आप जानते हैं कि आपकी कॉफी पीने की आदत रात की नींद पर असर डाल सकती है? जी हां, अगर आप बहुत जल्दी या ज्यादा कॉफी पीते हैं तो इससे आपकी नींद प्रभावित हो सकती है। आइए जानते हैं कि कॉफी का सेवन कैसे आपकी नींद को प्रभावित करता है।

कैफीन का समय : कैफीन का समय बहुत अहम होता है। अगर आप शाम या सुबह को कैफीन का सेवन करते हैं तो यह आपकी नींद को प्रभावित कर सकता है। कैफीन शरीर में काफी देर तक रहती है और इसे पूरी तरह से निकलने में समय लगता है। इसलिए, बेहतर होगा कि आप शाम 4 बजे के बाद कैफीन युक्त चीजों का सेवन न करें। इससे आपकी नींद पर कोई असर नहीं पड़ेगा और आप आराम से सो सकेंगे।

मात्रा पर ध्यान दें : कॉफी की मात्रा भी बहुत जरूरी होती है। ज्यादा कॉफी पीने से न केवल आपकी नींद खराब हो सकती है, बल्कि इससे सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। दिनभर में 2-3 कप कॉफी पीना ही पर्याप्त होता है। इससे आपको ऊर्जा मिलेगी और नींद पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। ज्यादा कॉफी पीने से सिरदर्द, बेचैनी और नींद न आने जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए इसकी मात्रा पर ध्यान देना जरूरी है।

खाली पेट कॉफी न पिएं : खाली पेट कॉफी पीना भी गलत है, क्योंकि इससे पेट पर दबाव पड़ता है और पाचन तंत्र प्रभावित होता है। इसके अलावा खाली पेट कॉफी पीने से एसिडिटी जैसी समस्याएं हो सकती हैं, जिससे नींद में खलल पड़ सकता है। बेहतर होगा कि आप सुबह उठते ही सबसे पहले थोड़ा पानी पिएं, फिर नाश्ता करें और उसके बाद ही कॉफी का सेवन करें। इससे आपका पाचन तंत्र सही रहेगा और आपको अच्छी नींद मिलेगी।

संगीत से बढ़ सकती है आपकी उत्पादकता, जानिए यह कैसे है मददगार

संगीत हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, जो केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं है। यह न केवल हमें आनंदित करता है, बल्कि हमारी उत्पादकता को भी बढ़ा सकता है। सही प्रकार का संगीत सुनने से हमारा मन शांत होता है और हम बेहतर तरीके से काम कर पाते हैं। आज हम जानेंगे कि कैसे संगीत हमारी उत्पादकता को बढ़ा सकता है और किन तरीकों से इसे अपने जीवन में शामिल किया जा सकता है।

काम करते समय सही धुन चुनें : काम करते समय सही धुन चुनना बहुत जरूरी है। धीमी और शांत धुन, जैसे शास्त्रीय या हल्के संगीत आपके दिमाग को शांत करते हैं और आपको अधिक ध्यान केंद्रित करने में मदद करते हैं। तेज और ऊर्जा से भरपूर धुन आपके ऊर्जा स्तर को बढ़ा सकती है, जिससे आप अधिक उत्साहित महसूस करते हैं। इस प्रकार की धुन आपके काम की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।

ध्यान लगाएं : ध्यान लगाने के लिए भी संगीत का उपयोग किया जा सकता है। कुछ विशेष प्रकार की धुनें, जैसे ध्यान संगीत या तरंग थेरेपी आपके मन को शांत करती हैं और ध्यान लगाने में मदद करती हैं। इससे आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और आप अधिक फोकस होकर काम कर पाते हैं। इस प्रकार की धुन सुनने से आपके दिमाग की क्षमता बढ़ती है और आप अपने कार्यों में अधिक समर्पण और ध्यान लगा पाते हैं।

तनाव कम करें : संगीत सुनने से तनाव कम करने में भी मदद मिलती है। जब आप किसी तनावपूर्ण स्थिति में हों तो कुछ मिनट के लिए आरामदायक धुन सुनना आपके मनोबल को बढ़ा सकता है और आपको शांत महसूस करवा सकता है। इससे आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है और आप अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से कर पाते हैं। यह तरीका न केवल आपको मानसिक शांति देता है, बल्कि आपके काम की गुणवत्ता को भी बेहतर बनाता है।

रचनात्मकता बढ़ाएं : रचनात्मक कार्यों के लिए भी संगीत बहुत अहम होता है। अगर आप कोई रचनात्मक कार्य कर रहे हों, जैसे कि लेखन, चित्रकारी या संगीत रचना आदि तो बैकग्राउंड में संगीत सुनने से आपकी रचनात्मकता बढ़ती है और नए विचार आते रहते हैं। इससे आपका काम ज्यादा आसानी से हो जाता है। सही प्रकार की धुन आपके मनोबल को बढ़ाती है और आपको प्रेरित करती है, जिससे आप अपने कार्य में पूरी तरह से डूब जाते हैं।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

एसआईआर की सुनवाई में कांग्रेस की 'निगरानी'

◆कांग्रेस पार्टी की हर दावे-आपत्ति पर नजर रखने की है तैयारी
◆मतदाता सूची को लेकर चुनावी साल में बढ़ेगी सियासी तपिश
◆एसआईआर में आपत्तियों के दौरान मौजूद रहेंगे कांग्रेस प्रतिनिधि

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर सियासी हलचल अब और तेज होने के आसार हैं। कांग्रेस ने संकेत दिया है कि एसआईआर के तहत होने वाली सुनवाई के दौरान वह अपने प्रतिनिधियों को मौजूद रखेगी। पार्टी का तर्क है कि मतदाता सूची से जुड़े दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और किसी भी पात्र मतदाता का नाम प्रभावित न हो। कांग्रेस का यह फैसला ऐसे समय आया है जब प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियां धीरे-धीरे रफ्तार पकड़ रही हैं। चुनावी राजनीति में मतदाता सूची महज प्रशासनिक दस्तावेज नहीं, बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया की बुनियाद होती है। ऐसे में एसआईआर की हर गतिविधि अब राजनीतिक दलों की निगाह में रहने वाली है।

कांग्रेस की रणनीति साफ दिखाई दे रही है। पार्टी सुनवाई के दौरान अपने प्रतिनिधियों के जरिए यह देखने की कोशिश करेगी कि दावे और आपत्तियों पर निर्धारित नियमों के अनुसार कार्रवाई हो रही है या नहीं। कांग्रेस को आशंका है कि प्रक्रिया के दौरान यदि किसी पात्र मतदाता का नाम सूची से हटता है या किसी आपत्ति का निस्तारण पारदर्शी तरीके से नहीं होता, तो उसका सीधा असर आने वाले विधानसभा चुनाव पर पड़ सकता है। यही कारण है कि पार्टी अब केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित रहने के बजाय प्रक्रिया के स्तर पर निगरानी बढ़ाने की तैयारी में है।

उत्तराखंड में एसआईआर अब सिर्फ प्रशासनिक कवायद नहीं रह गया है। इसके साथ राजनीतिक दलों की चिंता भी जुड़ गई है। चुनाव से पहले मतदाता सूची में होने वाला कोई भी बदलाव सीधे चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। कांग्रेस पहले भी एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाती रही है। पार्टी की कोशिश है कि सुनवाई के दौरान उसके प्रतिनिधि मौजूद रहें और जरूरत पड़ने पर आपत्ति या शिकायत को संबंधित स्तर तक पहुंचाया जा सके। भाजपा की ओर से इस पर क्या रुख अपनाया जाता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। यदि सत्तारूढ़ दल और विपक्ष एसआईआर को लेकर आमने-सामने आते हैं तो मतदाता सूची आने वाले महीनों में उत्तराखंड की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन सकती है।

कांग्रेस के लिए यह फैसला केवल प्रशासनिक निगरानी का विषय नहीं है। यह उसके संगठन की जमीनी क्षमता की भी परीक्षा है। प्रतिनिधि नियुक्त करना आसान है, लेकिन उन्हें हर स्तर पर सक्रिय रखना बड़ी चुनौती होगी। उन्हें मतदाता सूची समझनी होगी, दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया की जानकारी रखनी होगी और स्थानीय स्तर पर मतदाताओं के साथ संपर्क बनाए रखना होगा। यानी एसआईआर कांग्रेस के लिए संगठन को बूथ तक सक्रिय करने का अवसर भी बन सकता है। भाजपा लंबे समय से अपने बूथ संगठन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बताती रही है। ऐसे में कांग्रेस यदि एसआईआर की सुनवाई में अपने प्रतिनिधियों को सक्रिय करती है तो भाजपा को भी अपने संगठन की सक्रियता बनाए रखनी होगी।

2027 के चुनाव में मुकाबला केवल चुनावी सभाओं और नारों का नहीं होगा। मतदाता सूची से लेकर बूथ प्रबंधन तक हर स्तर पर राजनीतिक दलों की तैयारियां निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान यदि बड़ी संख्या में नाम हटने, जोड़ने या दावों-आपत्तियों को लेकर विवाद सामने आते हैं तो मामला राजनीतिक रंग ले सकता है। कांग्रेस इसे चुनावी पारदर्शिता का सवाल बनाएगी, जबकि भाजपा संभवत: प्रक्रिया को नियमों के तहत होने वाली सामान्य चुनावी कवायद बताएगी। लेकिन असली सवाल यह होगा कि अंतिम मतदाता सूची कितनी विश्वसनीय और स्वीकार्य बनती है।

2027 की चुनावी जंग अभी दूर है, लेकिन मतदाता सूची पर निगरानी की लड़ाई शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने सुनवाई में प्रतिनिधि उतारने का फैसला लेकर साफ कर दिया है कि वह एसआईआर को केवल सरकारी प्रक्रिया मानकर चुप बैठने वाली नहीं है। अब देखना होगा कि यह निगरानी लोकतांत्रिक पारदर्शिता तक सीमित रहती है या आने वाले दिनों में उत्तराखंड की सियासत का नया चुनावी रणक्षेत्र बन जाती है।

शब्द सामर्थ्य -042

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं :

1. लज्जत, जायका 2. मुकाबला, भेंट, होड़ 5. बंदी, कैद की सजा पाने वाला व्यक्ति 7. खल-पात्र, नाटक फिल्म आदि का बुरा पात्र 9. कामी, व्याभिचारी 10. इज्जत जाना, बेइज्जती होना (उपमा) 11. ऊटपटांग, विचित्र, कठिन 13. वैभव, ठाट-बाट 14. साथ, सहित 15. कामदेव की पत्नी, प्रेम 16. मैं का बहुवचन 17. दरवाजे-दरवाजे 20. एक राशि, मगर 22. नमी, सीड़, मुहर, ठप्पा 23. औषधालय, चिकित्सालय।

ऊपर से नीचे

1. आत्मनिर्भर, स्वालंबन भावना से युक्त, स्वाश्रित 2. वर्ष, बरस 3. राजी करना, रूठे हुए को खुश करना, प्रसन्न करना 4. नाटक फिल्म आदि का मुख्यपात्र 6. दीवानगी, पागलपन, 7. दो वस्तुओं के टकराने से उत्पन्न ध्वनि, बैर-विरोध, अनबन 8. खीरे की प्रजाति का एक फल 11. बेवकूफ, मूर्ख 12. बादल, मेघ 13. बहुत चालाक, होशियार 14. जिसका मत दूसरे से मिलता हो, 15. दांत, दंत 18. प्राप्ति, वस्तु आदि मिलने का प्रमाण पत्र 19. दंगा-फसाद, उपद्रव विप्लव 21. बचाव, सुरक्षा।

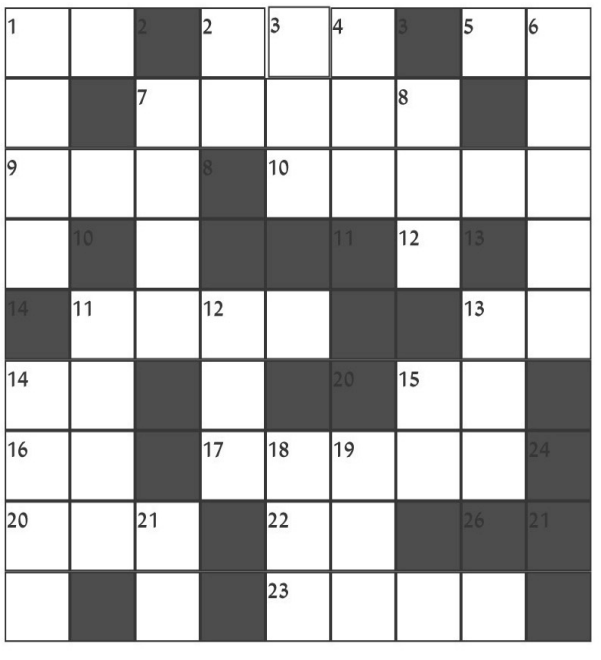

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 41 का हल

ग	ल	त	ज्ञ	■	■	खा	म	खाँ
णे	■	ल	■	झ	प	की	■	■
श	र	ब	त	■	रं	■	■	मि
■	ज	गा	ना	■	प	रा	का	ष्ठा
■	नी	र	■	वि	रा	ज	मा	न
ना	च	■	■	प	■	■	य	■
म	र	णा	स	न्न	■	पा	नी	■
ची	■	■	प	■	पा	■	■	भो
न	ज	रा	ना	■	स	मा	चा	र

साइकिलिंग को बनाएं अपनी दिनचर्या का हिस्सा, मिलेंगे ये फायदे

साइकिलिंग न केवल एक बेहतरीन एक्सरसाइज है, बल्कि यह हमारे जीवन को कई तरीकों से बेहतर बना सकती है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम अपने आसपास के माहौल को और करीब से महसूस करते हैं। इससे हमें ताजगी का एहसास होता है। इसके अलावा साइकिलिंग से हम नई जगहों का पता लगा सकते हैं और नए लोगों से मिल सकते हैं। आइए जानते हैं कि साइकिलिंग से क्या-क्या फायदे मिल सकते हैं।

तनाव से मिलेगी मुक्ति: साइकिलिंग करने से हमें तनाव से राहत मिल सकती है। जब हम साइकिल पर होते हैं तो हमारे दिमाग को एक नई ऊर्जा मिलती है। यह हमें ताजगी का एहसास कराता है और मानसिक थकान को दूर करता है। सड़क पर साइकिल चलाते समय हम अपने आसपास की सुंदरता को महसूस कर सकते हैं, जो हमारे मन को शांति देती है। इसके अलावा यह हमें नई जगहों का पता लगाने और नए अनुभव प्राप्त करने का मौका भी देती है।

सेहत के लिए है फायदेमंद: साइकिलिंग हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। यह हमारे दिल को मजबूत बनाती है, फेफड़ों की क्षमता बढ़ाती है और शरीर में खून का संचार बेहतर करती है। नियमित साइकिलिंग करने से हमारे शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और हम अधिक सक्रिय महसूस करते हैं। इसके अलावा यह हमारे वजन को नियंत्रित करने में भी मदद करती है और हमें फिट रखने में सहायक है।

पर्यावरण के लिए है अच्छा: साइकिलिंग पर्यावरण के लिए भी बहुत अच्छी होती है। जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण को कम करते हैं। इससे हवा साफ रहती है और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा साइकिल चलाने से हमें प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने का मौका मिलता है, जो हमारे मन को शांति देती है। यह न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे समाज और पर्यावरण के लिए एक अच्छा विकल्प है।

पैसे की बचत: साइकिलिंग आर्थिक रूप से भी फायदेमंद हो सकती है। जब हम साइकिल पर चलते हैं तो हमें पेट्रोल या डीजल पर खर्च नहीं करना पड़ता। इससे हमारे खर्चे कम होते हैं और हमारी बचत बढ़ती है। इसके अलावा साइकिल चलाने से हमें पार्किंग शुल्क भी नहीं देना पड़ता, जिससे हमारी और भी बचत होती है। यह हमारे लिए एक आर्थिक और पर्यावरण अनुकूल विकल्प है, जो हमारे बजट को भी संतुलित रखता है।

नई जगहों का करें पता: साइकिलिंग करते समय हम नई जगहों का पता लगा सकते हैं, जिनके बारे में शायद ही कभी सुना हो। इससे हमारा ज्ञान बढ़ता है और हम नए अनुभव प्राप्त करते हैं। इसके अलावा हम नए लोगों से मिल सकते हैं और नई दोस्ती कर सकते हैं। इस प्रकार साइकिलिंग हमारे जीवन में कई सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इसलिए इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना बहुत जरूरी है ताकि हम स्वस्थ रहें और जीवन का पूरा आनंद ले सकें।

क्या ऑफिस से घर आते ही पीठ में दर्द होता है? जानिए इसके कारण

अगर ऑफिस से घर आते ही आपकी पीठ में दर्द होने लगता है तो यह एक आम समस्या है। यह दर्द कई कारणों से हो सकता है, जैसे कि गलत तरीके से बैठना, भारी बैग उठाना या शारीरिक गतिविधियों की कमी। इस लेख में हम आपको कुछ ऐसे कारण बताएंगे, जिनके कारण आपको ऑफिस से घर आते ही पीठ में दर्द हो सकता है और इससे राहत पाने के तरीके भी जानेंगे।

गलत तरीके से बैठना: ऑफिस में लंबे समय तक काम करते समय अक्सर हम सही तरीके से नहीं बैठ पाते। गलत तरीके से बैठने से हमारी रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है, जिससे पीठ में दर्द हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि हमेशा सीधे बैठें और पीठ को सहारा देने वाले कुशन का उपयोग करें। इसके अलावा समय-समय पर थोड़ा टहलें और थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करें ताकि आपकी मांसपेशियों में खिंचाव बना रहे और दर्द से राहत मिल सके।

भारी बैग उठाना: अगर आप अपने लैपटॉप या अन्य जरूरी सामान एक भारी बैग में लेकर आते-जाते हैं तो इससे भी आपकी पीठ पर असर पड़ सकता है। भारी बैग उठाने से आपकी पीठ की मांसपेशियां खींच सकती हैं, जिससे दर्द हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि सामान को दोनों हाथों से समान रूप से उठाएं या फिर पहियों वाले बैग का उपयोग करें ताकि वजन का दबाव आपकी पीठ पर न पड़े। लंबे समय तक स्क्रीन के सामने रहना: लंबे समय तक कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन देखते रहने से भी आपकी पीठ पर असर पड़ सकता है। स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करते हुए आप अपनी मुद्रा पर ध्यान नहीं देते, जिससे रीढ़ की हड्डी पर दबाव पड़ता है। इस समस्या से बचने के लिए हर 30 मिनट बाद ब्रेक लें और अपनी आंखों को आराम दें। इस दौरान थोड़ा टहलें और अपनी पीठ को खींचे ताकि रक्त संचार बेहतर हो सके।

शारीरिक गतिविधियों की कमी: अगर आप रोजाना कुछ मिनट भी एक्सरसाइज नहीं करते तो इससे आपकी मांसपेशियां कमजोर हो सकती हैं, जिससे पीठ में दर्द हो सकता है। नियमित एक्सरसाइज करने से आपकी मांसपेशियों में ताकत आती है और दर्द की समस्या कम होती है। आप योग, पाइलेट्स या हल्की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जो आपकी पीठ और पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाती हैं। इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज से रक्त संचार भी बेहतर होता है।

मैं वहीं हूं, जहां मुझे होना चाहिए : अंजना सुखानी

बॉलीवुड अभिनेत्री अंजना सुखानी ने करियर में कई अलग-अलग तरह के किरदार निभाए हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन, सलमान खान, जॉन अब्राहम और अजय देवगन जैसे बड़े कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर किया है। अब वह अपनी नई फिल्म मैं वापस आऊंगा को लेकर चर्चा में हैं।

अंजना सुखानी ने कहा, मेरे लिए मैं वापस आऊंगा बेहद खास फिल्म है, क्योंकि इस फिल्म से इम्तियाज अली का नाम जुड़ा हुआ है। उनके साथ काम करना अपने आप में एक बड़ी बात है। दुनियाभर के कलाकार उनके साथ काम करने का सपना देखते हैं और मैं खुद को खुशकिस्मत मानती हूं कि मुझे यह मौका मिला। फिल्म की पूरी टीम के साथ काम करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा, खासकर नसीरुद्दीन शाह और दिलजीत दोसांझ के साथ। नसीर साहब के साथ काम करना किसी लाइव मास्टरक्लास जैसा अनुभव है। उन्हें देखकर ही अभिनय की बहुत सारी चीजें सीखी जा सकती हैं। फिल्म में वेदांग रैना और शरवरी के साथ काम करने के अनुभव पर अंजना ने कहा, मेरी कहानी फिल्म में अलग समय से जुड़ी हुई है, इसलिए उनके साथ ज्यादा सीन नहीं थे। हालांकि, ट्रेलर लॉन्च और शूटिंग के दौरान कुछ मुलाकातें जरूर हुईं। वेदांग और शरवरी दोनों ही बहुत प्रतिभाशाली कलाकार हैं। जब मैंने दोनों का पहला सीन देखा तो मैं काफी प्रभावित हुई। वे फिल्म में नई ऊर्जा लेकर आए हैं।

आज के समय में मॉडल, अभिनेता और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर्स के बीच की दूरी कम हो रही है। इस बदलाव पर अंजना ने कहा कि अब चीजें काफी बदल गई हैं। पहले भी मॉडल फिल्मों में आते थे और अभिनेता मॉडलिंग करते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया से जुड़े लोग भी अभिनय की दुनिया में आ रहे हैं। किसी व्यक्ति में टैलेंट है और वह सच में अभिनेता बनना चाहता है तो उसे मौका मिलना चाहिए। आखिर में सबसे जरूरी चीज यह है कि कलाकार अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित कर पाता है या नहीं।

मल्टीस्टारर फिल्मों के बढ़ते चलन पर अंजना ने कहा, सबसे जरूरी बात फिल्म की सफलता है। फिल्म छोटी हो या बड़ी और उसमें कितने कलाकार हों, इससे ज्यादा मायने रखता है कि दर्शक उसे पसंद करते हैं या नहीं। जब कोई फिल्म सफल होती है तो इसका फायदा सिर्फ कलाकारों को नहीं बल्कि पूरी टीम को मिलता है। टेक्नीशियन, लाइटिंग टीम, स्पॉट बॉय और प्रोडक्शन से जुड़े सभी लोगों को काम मिलता है। मेरी दर्शकों से अपील है कि वे फिल्मों को थिएटर में जाकर जरूर देखें।

अमिताभ बच्चन के साथ स्क्रीन शेयर करने के अनुभव को याद करते हुए अंजना ने कहा, यह मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। करियर शुरू होने के कुछ सालों बाद मुझे अमिताभ बच्चन के साथ विज्ञापन करने का मौका मिला और बाद में राम गोपाल वर्मा की फिल्म डिपार्टमेंट में भी उनके साथ काम किया। अमिताभ बच्चन और इम्तियाज अली जैसे दिग्गजों के साथ काम करना बड़ी उपलब्धियों में शामिल है।

हिंदी और साउथ सिनेमा के अंतर पर अंजना ने कहा कि दोनों जगहों की कहानी कहने का तरीका अलग है। हिंदी फिल्में अक्सर पूरे देश के दर्शकों को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं, जबकि क्षेत्रीय सिनेमा अपनी भाषा और संस्कृति से ज्यादा जुड़ा होता है। भारत की यही विविधता उसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है और कलाकारों को अलग-अलग भाषाओं में काम करने का मौका मिलना एक अच्छी बात है।

फौजी- इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है

फौजी इस साल की सबसे बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार प्रभास मुख्य भूमिका में हैं. फिल्म की घोषणा के बाद से ही दर्शकों में इसे लेकर जबरदस्त उत्साह है, जिससे यह आने वाली सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई हैय इस उत्साह को और बढ़ाते हुए, प्रभास ने अब एक शानदार पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज डेट का एलान किया है. जारी पोस्टर में प्रभास खून से लथपथ हालत में एक चट्टान पर बैठे नजर आ रहे हैं; उनके आस-पास बेजान लाशें बिखरी हुई हैं और उन्होंने हाथ में बंदूक थाम रखी है. अ बटालियन हू फाइट्स अलोन (टैगलाइन वाला यह पोस्टर एक्शन, कुर्बानी और बगावत से भरपूर एक जबरदस्त वॉर ड्रामा की ओर इशारा करता है. यह पोस्टर फिल्म की जबरदस्त दुनिया की एक झलक दिखाता है. इस दमदार पोस्टर को साझा करते हुए मेकर्स ने कैप्शन में लिखा है, अज्ञातपर्व का अंत. बगावत की शुरुआत. फौजी दुनिया भर में 3 दिसंबर 2026 को बड़े पैमाने पर रिलीज होगी.

प्रभास की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अक्षय कुमार, विद्या बालन और राशी खन्ना की अनटाइटल्ड फिल्म से टकराएगी. ट्रेड एनालिस्ट के अनुसार, अक्षय की यह फिल्म प्रभास की फिल्म रिलीज के एक दिन बाद सिनेमाघरों में दस्तक देगी. इस फ़िल्म के डायरेक्टर अनीस बज्मी हैं. इस मुकाबले में अजय देवगन की फिल्म रेंजर भी शामिल है, जिसे जगन शक्ति ने डायरेक्ट किया है. यह फिल्म भी उसी दिन यानी 4 दिसंबर को रिलीज होने की तैयारी में है, जिससे बॉक्स ऑफिस पर तीन फिल्मों के बीच टक्कर होने की संभावना बन गई है. यह इंडियाना जोन्स जैसी एडवेंचर फिल्म है. नु राघवपुडी के निर्देशन में बन रही फिल्म फौजी की कहानी आजादी से पहले के भारत की पृष्ठभूमि पर आधारित बताई जा रही है. उम्मीद है कि इस फिल्म में इतिहास, देशभक्ति, रोमांस और एक्शन का मेल देखने को मिलेगा, जिसमें प्रभास एक ऐसे किरदार में नजर आएंगे.

शहीद हवलदार कुंदन सिंह को 26वीं पुण्यतिथि पर किया याद

पिथौरागढ़(आरएनएस)। ऑपरेशन विजय के वीर शहीद 4 कुमाऊं रेजीमेंट के हवलदार कुंदन सिंह खड़ायत को 26वीं पुण्यतिथि पर याद किया गया। मडेगांव में स्थित स्मारक में परिजनों, पूर्व सैनिकों और स्थानीय लोगों ने शहीद को पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। वर्ष 2000 में कश्मीर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों के दौरान देश की रक्षा करते हुए हवलदार कुंदन सिंह खड़ायत ने अदम्य साहस का परिचय दिया और अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। 12 कुमाऊं रेजीमेंट के मानद लेफ्टिनेंट तारा सिंह व सूबेदार विनोद सिंह के नेतृत्व में पहुंचे जवानों ने सैन्य परंपरा के अनुसार शहीद को श्रद्धांजलि दी। पूर्व सैनिकों की ओर से सूबेदार मेजर रिटायर सुरेश पुनेरा ने पुष्पचक्र अर्पित किए।इस दौरान में शहीद की माता खीमा देवी को पूर्व सैनिक संगठन की ओर से शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। इस दौरान पूर्व सैनिक संगठन के उपाध्यक्ष रमेश सिंह महर,सीनियर सिटीजन संगठन के अध्यक्ष दयानंद भट्ट, भाजपा नेता वीरेंद्र बल्दिया, यूकेडी नेता चंद्रशेखर कापड़ी,जयंती देवी, भूपेंद्र बोहरा, लक्ष्मण सिंह गोबड़ी, नंदा सिंह बिष्ट, परमानंद भट्ट, जीत सिंह गोबड़ी, देव सिंह भटिया, दयाल सिंह, श्याम विश्वकर्मा, धर्म सिंह रसूनी, कमान सिंह, भूपाल सिंह, कैप्टन रिटायर विक्रम सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

चिल्ड्रन पार्क के टेंडर में अनुभव और टर्नओवर की शर्तों पर उठे सवाल

नई टिहरी(आरएनएस)। नगर पंचायत चमियाला में करीब 33.86 लाख की लागत से प्रस्तावित चिल्ड्रन पार्क के निर्माण के लिए जारी निविदा की शर्तों को लेकर विवाद गहरा गया। ठेकेदार चंदन सिंह चौहान ने अनुभव और टर्नओवर की शर्तों को लेकर जिलाधिकारी से शिकायत की है।हालांकि नगर पंचायत ने शिकायत के बाद शर्तों को बदल दिया है।उन्होंने आरोप लगाया कि काम की अनुमानित लागत की तुलना में निविदा में अनुभव और टर्नओवर की शर्तें अधिक रखी गई है। 33.86 लाख के निर्माण कार्य के लिए 50 लाख तक के कार्य का अनुभव अनिवार्य किया गया था। वहीं निविदा में 1.50 करोड़ के टर्नओवर की शर्त भी रखी गई थी। उनका आरोप है कि इससे छोटे ठेकेदारों के लिए निविदा प्रक्रिया में शामिल होना मुश्किल हो रहा है।मामले में जिलाधिकारी के साथ ही मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर जांच और नियमों के पालन की मांग की। आरोप लगाया कि पहले इस तरह के कार्यों में एकल निविदा प्रक्रिया अपनाई जाती थी लेकिन इस बार नगर पंचायत की ओर से दोहरी निविदा प्रक्रिया अपनाई गई। नगर पंचायत चमियाला के ईओ मानवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि शिकायत का संज्ञान लेते हुए निविदा की शर्तों में संशोधन कर दिया गया है। अब कार्य अनुभव की सीमा 50 लाख से घटाकर 35 लाख रुपये कर दी गई है। 1.50 करोड़ रुपये के टर्नओवर की बाध्यता समाप्त कर दी गई है।

सू- दोकू क्र.042

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.41 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में जूनोटिक रोगों की निगरानी पर प्रशिक्षण

अल्मोड़ा(आरएनएस)। सोबन सिंह जीना राजकीय आयुर्विज्ञान एवं शोध संस्थान में जूनोटिक बीमारियों की निगरानी, रोकथाम और नियंत्रण को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक दिवसीय इंडक्शन प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। सूक्ष्मजीव विज्ञान विभाग और राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र (एनसीडीसी) के राष्ट्रीय जूनोटिक रोग रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम के तहत स्थापित सेंटिनल सर्विलांस साइट फॉर जूनोज की ओर से आयोजित कार्यशाला में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों को वन हेल्थ अवधारणा के तहत रोगों की शीघ्र पहचान और प्रभावी निगरानी का प्रशिक्षण दिया गया।

कार्यशाला का उद्घाटन संस्थान के प्राचार्य प्रो. (डॉ.) जी.एस. तितियाल ने किया। उन्होंने कहा कि स्क्रब टाइफस, रेबीज, ब्रूसेलोसिस और लेप्टोस्पायरोसिस जैसे पशुजनित संक्रामक रोग पर्वतीय क्षेत्रों में जनस्वास्थ्य के लिए बड़ी चुनौती हैं। इन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के समन्वित वन हेल्थ दृष्टिकोण को मजबूत करना आवश्यक है।

चिकित्सा अधीक्षक डॉ. दिनेश पुनेरा ने अस्पताल की ओपीडी और आईपीडी में आने वाले संदिग्ध मरीजों की समय पर पहचान, जांच और मानक उपचार प्रोटोकॉल के पालन पर जोर दिया। नोडल अधिकारी डॉ. विक्रांत नेगी ने कुमाऊं मंडल में जूनोटिक रोगों की वर्तमान स्थिति, निगरानी प्रणाली और भविष्य की कार्ययोजना प्रस्तुत की।

प्रशिक्षण के दौरान मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉ. अशोक कुमार ने मानक केस डेफिनिशन के आधार पर रोगों की शीघ्र पहचान की जानकारी दी, जबकि कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉ. अंशुल ममगाईं ने डिटेक्ट, रिपोर्ट, रिस्पॉन्ड रणनीति पर व्याख्यान दिया। डॉ. रवि सैनी के निर्देशन में केस रिकॉर्ड फॉर्म भरने का व्यावहारिक प्रशिक्षण भी कराया गया। कार्यशाला का संचालन मेडिकल सोशल वेलफेयर ऑफिसर हेम बहुगुणा ने किया। कार्यक्रम में डॉ. उर्मिला पलड़िया, डॉ. एम. अनुराधा, डॉ. अमित आर्य, डॉ. नौशीन, आईडीएसपी के एपिडेमियोलॉजिस्ट नरेंद्र, माइक्रोबायोलॉजिस्ट अभिषेक मेहरा सहित विभिन्न विभागों के संकाय सदस्य, रेजिडेंट डॉक्टर, नर्सिंग अधिकारी और प्रयोगशाला प्राविधिक मौजूद रहे। समापन सत्र में प्रतिभागियों का प्री एवं पोस्ट टेस्ट मूल्यांकन किया गया, केस डिस्कशन आयोजित हुए और सफल प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

सरहद पर तैनात भाइयों के लिए भेजी राखियां

अल्मोड़ा(आरएनएस)। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर महिला कल्याण संस्था ने अपनी वर्षों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए इस बार भी सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए 3000 राखियां सेना अधिकारियों को भेंट कीं। संस्था की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल अमित कुमार और सूबेदार मेजर सतनाम सिंह को राखियां सौंपते हुए सैनिकों के प्रति सम्मान और शुभकामनाएं प्रेषित की गईं। सेना अधिकारियों ने संस्था की महिलाओं को भरोसा दिलाया कि सभी राखियां समय पर देश की सीमाओं पर तैनात जवानों तक पहुंचाई जाएंगी। उन्होंने संस्था की इस भावनात्मक पहल की सराहना करते हुए कहा कि समाज का यह स्नेह और सम्मान सैनिकों का मनोबल बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महिला कल्याण संस्था की महिलाओं ने देश की रक्षा में जुटे सैनिकों के उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु और सुरक्षित जीवन की कामना करते हुए कहा कि जवान अपने परिवारों से दूर रहकर राष्ट्र की सुरक्षा का दायित्व निभाते हैं। ऐसे में रक्षाबंधन पर राखी भेजना उनके प्रति पूरे समाज के सम्मान, विश्वास और आत्मीयता का प्रतीक है।

पीएम पोषण के रियलटाइम मॉनिटरिंग में गड़बड़ी, छह स्कूलों से मांगा स्पष्टीकरण

रुद्रप्रयाग(आरएनएस)। प्रधानमंत्री पोषण योजना की ऑटोमैटिक रियलटाइम मॉनिटरिंग सिस्टम की समीक्षा में छह विद्यालयों के भोजन ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों की गलत संख्या भेजे जाने का मामला सामने आया है। मुख्य शिक्षा अधिकारी अजय कुमार चौधरी ने संबंधित छह स्कूलों के प्रधानाचार्यों और प्रधानाध्यापकों से स्पष्टीकरण तलब किया है। ऑटोमैटिक रियलटाइम मॉनिटरिंग सिस्टम की समीक्षा में पाया गया कि इन विद्यालयों ने पंजीकृत छात्र संख्या के सापेक्ष भोजन करने वाले विद्यार्थियों की गलत संख्या एसएमएस के माध्यम से भेजी। इन विद्यालयों में ऊखीमठ का जीआईसी नारायणकोटि, जखोली का जनता जूनियर हाईस्कूल विनोधारा तथा अगस्त्यमुनि के उच्च प्राथमिक विद्यालय सिल्ला, प्राथमिक विद्यालय कौशलपुर, प्राथमिक विद्यालय बौठा धनपुर और राजकीय इंटर कॉलेज कमसाल शामिल है। मुख्य शिक्षा अधिकारी अजय कुमार चौधरी ने सभी खंड एवं उप शिक्षा अधिकारियों को संबंधित विद्यालयों से स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।

उचित मुआवजे के लिए श्रमिकों ने निकाला जुलूस

चमोली(आरएनएस)। टीएचडीसी की पीपलकोटी-विष्णुगाड जल विद्युत परियोजना की निर्माणाधीन टनल हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिकों के आश्रितों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर श्रमिकों ने जुलूस निकाला। उन्होंने टीएचडीसी गेट पर कंपनी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक मृतकों के आश्रितों को मुआवजा नहीं मिल जाता आंदोलन को जारी रखा जाएगा। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया के नेतृत्व में एचसीसी वर्कस यूनियन मायापुर मायापुर पीपलकोटी के श्रमिकों ने जुलूस निकाला। श्रमिकों ने कहा कि हादसे में जान गंवाने वाले श्रमिक परिवारों का मुख्य सहारा थे। उनके परिवारों के सामने आर्थिक संकट गहरा गया है। प्रभावित परिवारों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेस्क्यू अभियान पूरा हो चुका है लेकिन प्रभावित परिवारों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने टीएचडीसी प्रबंधन से जल्द वार्ता कर मुआवजे के मुद्दे का समाधान करने की मांग की है।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को भेजा ज्ञापन

हरिद्वार(आरएनएस)। चतुर्थ श्रेणी राज्य कर्मचारी संघ चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं उत्तराखंड ने आंदोलन के तीसरे चरण में दर्जाधारी ओमप्रकाश जमदग्नि और मेयर किरन जैसल के माध्यम से मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञापन भेजा। कर्मचारियों ने पदोन्नति समेत विभिन्न मांगों का जल्द निस्तारण करने की मांग की। संघ ने चेतावनी दी कि मांगों पर कार्रवाई नहीं होने पर 21 अगस्त को आंदोलन के चौथे चरण में महानिदेशक कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी और धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष दिनेश लखेड़ा, महामंत्री सुनील अधिकारी, प्रदेश संगठन सचिव दिनेश गुसाईं और विपिन नेगी, प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरीश पंत तथा जिला मंत्री राकेश भंवर ने कहा कि कर्मचारी संघ शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहा है, लेकिन महानिदेशालय और शासन की ओर से मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संगठन लगातार शासन को अवगत करा रहा है कि कर्मचारियों की पदोन्नति से सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इसके बावजूद कर्मचारियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पदोन्नति, पौष्टिक आहार भत्ता, वर्दी भत्ता और धुलाई भत्ता समेत कई मांगें लंबे समय से लंबित हैं। कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि मांगों का समाधान नहीं होने से उनका उत्पीड़न और शोषण हो रहा है। संघ ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मामले में हस्तक्षेप कर कर्मचारियों को न्याय दिलाने की मांग की है। प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र तेश्वर, उप शाखा मंत्री ऋषिकुल अजय कुमार, अध्यक्ष गुरुकुल ताजबर सिंह, मनीष पंवार, संगठन सचिव नितिन कुमार और उपाध्यक्ष बाला देवी ने कहा कि शासनादेश जारी होने के बावजूद कर्मचारियों को अब तक वर्दी भत्ता वेतन में नहीं दिया गया है। वहीं, वर्षों से धुलाई भत्ते में भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि नर्सिंग संवर्ग को पौष्टिक आहार भत्ता दिया जा रहा है, जबकि उनके साथ ड्यूटी करने वाले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को यह सुविधा नहीं मिल रही है। उन्होंने कहा कि अब कर्मचारियों के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई लड़ी जा रही है। मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री की ओर से मांगों के समाधान का आश्वासन मिलने पर आंदोलन रोका जा सकता है। अन्यथा 21 अगस्त को महानिदेशक कार्यालय के बाहर नारेबाजी और धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। वार्ता के दौरान पदोन्नति, पौष्टिक आहार भत्ता, वर्दी भत्ता और धुलाई भत्ते की मांगों का समाधान नहीं होने पर आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

धर्मपुर विधानसभा में एसआईआर को लेकर कांग्रेस की महत्वपूर्ण बैठक

संवाददाता

देहरादून। विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में एसआईआर प्रक्रिया से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश महासचिव व समन्वयक धर्मपुर विधानसभा राजेन्द्र शाह ने उपस्थित पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान आने वाली संभावित विसंगतियों, मतदाताओं के नामों के सत्यापन, आवश्यक दस्तावेजों तथा बूथ स्तर पर समन्वय के संबंध में जानकारी दी। शाह ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदाता सूची का शुद्ध एवं त्रुटिरहित होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी जिम्मेदारी और सजगता के साथ बूथ स्तर पर कार्य करें। शाह ने कहा कि बूथ नंबर 61 पर आकाश नामक व्यक्ति द्वारा फर्जी तरीके से दर्जनों नामों पर आपत्ति लगाई गई है परंतु इस नाम का व्यक्ति न तो उस विधानसभा से संबंधित है और न ही उसका कोई अता पता है।

अखिलेश उनियाल ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि कांग्रेस के बीएलए-2 अपने-अपने बूथों पर सक्रियता के साथ कार्य करें तथा बीएलओ के साथ समन्वय स्थापित करते हुए पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सुरक्षित रखने और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी अथवा विसंगति की स्थिति में तत्काल संगठन को अवगत कराएं। बैठक में उपस्थित कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुए कांग्रेस की नेता व सह-समन्वयक एडवोकेट सुनीता प्रकाश ने कार्यकर्ताओं से एसआईआर प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभावी ढंग से कार्य करने की अपील की। बैठक में प्रदेश सचिव एवं सहसमन्वयक सुनीता प्रकाश, तीनों ब्लाकों के अध्यक्ष मुकीम अहमद पार्षद, ललित भद्री एवं विरेन्द्र पंवार, पूर्व पार्षद हरिप्रसाद भट्ट, रमेश कुमार मंगू, पार्षद एतात खान, पार्षद जाहिद अंसारी, पूर्व पार्षद अनूप कपूर, बीएलए-1 आशीष वर्मा, नवीन रमोला, गिरीश सुन्द्रियाल, रामकिशन यादव, सूरत सिंह लांबा, हितेश चौहान, सरवर अहमद, पुनीत नेगी, मो. साहिन, सुल्तान पठान, डीएस क्षेत्री, धन बहादुर थापा, डीएस गुसांई, सुरेन्द्र भटनागर, यशपाल धीमान आदि उपस्थित थे।

इस्टाग्राम पर हुई दोस्ती ठगे दो लाख

संवाददाता

देहरादून। इस्टाग्राम पर दोस्ती होने के बाद दो लाख रूपये ठगने के मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। प्राप्त जानकारी के अनुसार डोईवाला निवासी महिला ने डोईवाला कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि इस्टाग्राम पर उसकी दोस्ती सेवाला जिला दतिया मध्य प्रदेश के साथ हुई। उसने उसकी फोटो को बिना उसकी अनुमति के इस्टाग्राम आईडी पर पोस्ट कर व दोस्ती के जाल में फंसाकर दो लाख रूपये लेकर वापस नहीं किये गये व उसके परिवार के नम्बर इस्टाग्राम पर डालकर परेशान किया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

'पुलिस विभाग वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं पर जरूरी कदम उठाने हेतु त्रैमासिक बैठकों का आयोजन करेगा'

संवाददाता

देहरादून। वरिष्ठ नागरिकों के साथ पुलिस विभाग पारस्परिक सामंजस्य से इनकी समस्याओं पर जरूरी कदम उठाने, सुझाव संकलित करने हेतु त्रैमासिक बैठकों का आयोजन करेगा।

यह आश्वासन आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र डोभाल ने विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस पर संयुक्त नागरिक संगठन की पहल पर आयोजित संवाद में दिया।एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि बुजुर्गों की कठिनाइयों के त्वरित समाधान के लिए विभाग सभी कदम उठाएगा,किसी भी कठिनाई में वरिष्ठ नागरिक किसी भी समय संपर्क कर विभाग की मदद ले सकते हैं। संवाद में दून के वरिष्ट नागरिकों ने सुझाव दिए की राज्य में लागू उत्तराखंड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली 2011 के प्राविधानों के अंतर्गत थानावर बुजुर्गों के साथ मासिक बैठक आयोजित की जानी जरूरी है।एकल तथा युगल बुजुर्ग दंपत्तियों की सुरक्षा/सहायता हेतु व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाना चाहिए। जिस पर अधिकारियों ने सहमति प्रकट की।संवाद में रणजीत सिंह कैंतूरा,विनोद प्रकाश नौटियाल,सुलोचना भट्ट,राधा तिवारी,डा.एस स्वामी चंद्रा,जगमोहन मेहंदीरत्ता,उमेश्वर सिंह रावत,गिरीश चंद्र भट्ट,ताराचंद गुप्ता,डॉ एस एस खेड़ा,दिनेश भंडारी,अवधेश शर्मा, खुशवीर सिंह,उमेश सक्सेना,मुकेश नारायण शर्मा,नरेश चंद्र कुलाश्री,एस पी नौटियाल आदि शामिल थे।

पुलिस ने की पीजी/हॉस्टल में आकस्मिक चैकिंग

◆चार होस्टल संचालकों को दिया नोटिस, वहीं चार हिरासत में

हमारे संवाददाता

देहरादून। पढ़ाई की आड़ में शहर में हुड़दंग करने वाले छात्रों पर नकेल कसने के लिए पुलिस द्वारा बीती रात प्रेमनगर क्षेत्र के होस्टलों में आकस्मिक चैंकिग की गयी। 4 होस्टलों में अनियमितता पाये जाने पर पुलिस होस्टल संचालकों को नोटिस दिया तथा अनावश्यक घूम रहे युवको को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी गयी।

पढाई की आड में हुडदंग करने तथा आपराधिक गतिविधियों में लिप्त छात्र/छात्राओं को चिन्हित कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही करने के उद्देश्य से पुलिस द्वारा बीती रात प्रेमनगर क्षेत्र में स्थित हास्टल/पीजी में आकस्मिक रूप से चैकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सभी प्रतिष्ठान संचालको से उनके प्रतिष्ठान में रहने वाले छात्र/छात्राओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करते हुए उन्हें अपने प्रतिष्ठान में रहने वाले छात्र/छात्राओं का शत-प्रतिशत सत्यापन कराने तथा प्रतिष्ठानों में अनिवार्य रूप से सीसीटीवीं कैमरे लगवाने की हिदायत दी गई। साथ ही सभी प्रतिष्ठान संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों में निवासरत छात्र/छात्राओं के प्रवेश की समयसीमा रात्रि 10 बजे निर्धारित करने, प्रतिष्ठान में आने वाले बाहरी व्यक्तियों को सत्यापन के बाद ही प्रतिष्ठान में आने की अनुमति देने तथा आने जाने वाले व्यक्तियों का सम्पूर्ण ब्यौरा अपने पास सुरक्षित रखने के निर्देश दिये गये। साथ ही प्रतिष्ठान में रहने वाले छात्र/छात्राओं के रात्रि में अनावश्यक रूप से घूमते हुए पाये जाने, किसी आपराधिक गतिविधि में संलिप्तता अथवा प्रतिष्ठानों में छात्रों द्वारा नशीले पदार्थो के सेवन से सम्बन्धित किसी भी शिकायत पर सम्बन्धित छात्र के साथ-साथ प्रतिष्ठान संचालक के खिलाफ भी वैधानिक कार्यवाही की चेतावनी दी गई। अभियान के दौरान 4 हॉस्टल में अनियमितता पाए जाने पर पुलिस द्वारा संबंधित हॉस्टल संचालकों को नोटिस देकर तय समयसीमा के अंदर सभी अनियमितताओं को दूर करने के निर्देश दिए गए, साथ ही चेकिंग के दौरान देर रात्रि में आवश्यक रूप से घूम रहे 4 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ हेतु थाने लाया गया।

एसआईआर में दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग करेंगे अधिकारी

संवाददाता

देहरादून। मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरूषोत्तम ने निर्देश दिये कि एसआईआर में दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की अधिकारी मॉनिटरिंग करेंगे।

आज यहां भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर)-2026 के तहत दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉ. बीवीआरसी पुरुषोत्तम द्वारा प्रशासनिक सेवा के 9 आईएएस / पीसीएस अधिकारियों को पर्यवेक्षण अधिकारी के रूप में तैनात किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार हरिद्वार जनपद में डॉ. संदीप तिवारी, ललित नारायण मिश्र, नन्द कुमार और गोपाल राम बिनवाल को पर्यवेक्षण अधिकारी बनाया गया है। नैनीताल जनपद में संजय कुमार एवं विनीत तोमर तथा ऊधम सिंह नगर जनपद में प्रकाश चन्द्र दुम्का, जय किशन एवं दिवेश शाशनी को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। पर्यवेक्षण अधिकारियों द्वारा संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची से संबंधित दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया, जिसमें नोटिस वितरण, तामीली एवं सुनवाई की निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए गुणवत्तापूर्ण निस्तारण प्रक्रिया की निगरानी की जाएगी। इन अधिकारियों को अपने दैनिक निरीक्षण की आख्या संबंधित मण्डलायुक्त के माध्यम से मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को सप्ताह में दो बार प्रस्तुत करनी होगी। आदेश के अनुसार निर्धारित पुनरीक्षण अवधि तक नामित अधिकारी आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण एवं अनुशासन के अधीन रहेंगे। मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

बंद घर में हुई चोरी का खुलासा, शातिर चोर गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

चमोली। बंद घर में हुई चोरी का खुलासा करते हुए पुलिस ने एक शातिर को गिरफ्तार कर लिया है। जिसके पास से चुराये गये जेवरात व अन्य सामान बरामद किया गया है।

जानकारी के अनुसार बीती 20 अगस्त को सत्यपाल सिंह चौधरी पुत्र जयेंद्र सिंह, निवासी वार्ड नंबर-6, निकट केशवास स्कूल, गौचर, थाना कर्णप्रयाग, जनपद चमोली द्वारा कोतवाली कर्णप्रयाग में तहरीर देकर बताया कि वह अपना उपचार कराने देहरादून गए हुए थे। वापस गौचर स्थित अपने घर पहुंचने पर देखा कि अज्ञात चोर द्वारा घर का ताला तोड़कर उनके नाती के 2 जोड़ी चांदी के कंगन, 2 जोड़ी चांदी की पायल, एक सूटकेस एवं एक जैकेट चोरी कर लिया गया है। बताया कि चोर द्वारा घर की अलमारियों को भी तोड़कर नुकसान पहुंचाया गया था। मामले मे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी गयी। चोर की तलाश में जुटी पुलिस टीम द्वारा घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को बारीकी से खंगाला गया। जांच के दौरान दिनांक 14-15 अगस्त की रात्रि लगभग 11 बजे से 4 बजे के मध्य एक संदिग्ध व्यक्ति ग्रिफ चौक से पीड़ित के घर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने संदिग्ध की फोटो एवं वीडियो फुटेज के आधार पर उसकी तलाश शुरू कर दी गयी। पुलिस टीम के अथक प्रयासों के फलस्वरूप आज सुबह लगभग 7.30 बजे गौचर-रुद्रप्रयाग मोटर मार्ग पर सरस्वती विद्या मंदिर के आगे स्थित प्रतीक्षालय के पास संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम उमेद सिंह भंडारी पुत्र स्वर्गीय दलबीर सिंह भंडारी निवासी ग्राम कंडारा, थाना कर्णप्रयाग, जनपद चमोली बताया। जिसके कब्जे से चोरी किया गया 2 जोड़ी चांदी के कंगन, 2 जोड़ी चांदी की पायल, एक सूटकेस एवं एक जैकेट बरामद हुआ। पूछताछ में आरोपी ने गौचर स्थित उक्त घर में चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। बहरहाल पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया है। जांच में यह भी प्रकाश में आया कि गिरफ्तार आरोपी चोरी की घटनाओं का अभ्यस्त अपराधी है। उसके खिलाफ जनपद पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग एवं चमोली के विभिन्न थानों में चोरी एवं अन्य धाराओं में कई मुकदमें दर्ज है।

❑चुराये गये जेवरात व अन्य सामान बरामद

सरकार महिला, युवा और ग्रामीण उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए समर्पित : धामी

❑मुख्यमंत्री उद्यमशाला चौपाल- 2026 में मुख्यमंत्री ने किया लखपति दीदियों और महिला उद्यमियों का सम्मान

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के अंतर्गत चौपाल 2026 का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के माध्यम से अब तक प्रदेश में 13 हजार से अधिक उद्यमियों को सहयोग दिया जा चुका है। साथ ही 8 हजार से अधिक महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों की सदस्यों को उद्यमिता और आजीविका के अवसरों से जोड़ा गया है। उद्घाटन सत्र में उन्होंने देहरादून के आईटी पार्क स्थित 13 गांव में प्रदेश के समस्त जनपदों के स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद विपणण के लिए राज्य स्तरीय विपणन केंद्र खोलने की घोषणा की है। उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हमारे गांव प्रदेश के विकास में सहभागी ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि अपने सामर्थ्य और परिश्रम के बल पर आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के

निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के उत्साही युवाओं, साहसी मातृशक्ति में कुछ कर गुजरने की इच्छा और हुनर है, इसी तरह प्रदेश के स्थानीय उत्पादों में देश-दुनिया के बाजार तक पहुंचने की पूरी क्षमता है। जरूरत केवल इस बात कि है कि हुनर को सही दिशा मिले। इसी सोच के साथ प्रदेश सरकार ने 'मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना' को आगे बढ़ाने का काम किया है। योजना के जरिए सरकार का प्रयास है कि उत्तराखण्ड का युवा रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बने। साथ ही किसानों और महिलाओं की आर्थिक स्थित मजबूत हो। मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना इसी सोच को धरातल पर उतारने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने कहा कि इस योजना के माध्यम से ग्रामीण उद्यमियों को अपना व्यवसाय शुरू करने और आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, आर्थिक सहयोग, तकनीकी मार्गदर्शन और बाजार से जुड़ने में मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जहां एक ओर प्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से 5 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 70 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जा चुका है। वहीं, 3 लाख से अधिक बहने लखपति दीदी बनने में सफल रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की मातृशक्ति पहाड़ी मसालों से लेकर मंडुवा, झंगोरा, दालों, शहद, अचार, जैम, हस्तशिल्प, ऊनी उत्पादों और स्थानीय कला तक को व्यवसाय का रूप दे रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि सरकार गांव के उत्पादों को देश के बड़े शहरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। इसी दिशा में काम करते हुए हाउस ऑफ हिमालयाज नामक अंब्रेला ब्रांड तैयार किया गया है। इसीलिए आज प्रदेश में ग्रामीण हाट, विपणन केंद्र, कलेक्शन सेंटर और एग्री सर्विस सेंटर जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है, ताकि किसान और उद्यमी को अपने उत्पाद के लिए बेहतर बाजार और बेहतर मूल्य मिल सके। उन्होंने कहा कि ग्रामीण उद्यमिता का एक बड़ा उद्देश्य पलायन को रोकना भी है। सरकार चाहती है कि युवा रोजगार की तलाश में अपने गांव को छोड़ने के लिए मजबूर न हों। क्योंकि गांव मजबूत होगा तो उत्तराखण्ड मजबूत होगा। आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री ने लखपति दीदी और महिला उद्यमियों को भी सम्मानित किया। साथ ही उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत तैयार की गई पुस्तक, वार्षिक रिपोर्ट का भी विमोचन किया। साथ ही एकीकृत कृषि कलस्टर आधारभूत प्रशिक्षण एवं मॉड्यूल और शिशु एवं लघु बाल आहार मॉड्यूल के साथ ही महिलाओं एचं बच्चों में एनीमिया की रोकथाम एवं प्रबंधन मॉडयूल का भी लोकार्पण किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी, गणेश जोशी, खजान दास, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, विधायक उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सविता कपूर, सचिव ग्राम्य विकास धीराज गर्ब्याल एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मेडिकल स्टोर से नशीले इंजेक्शन एवं नशीले दवाए बरामद

◆मेडिकल स्टोर सील, की गयी वैधानिक कार्यवाही

हमारे संवाददाता

देहरादून। नशे के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए एसटीएफ व औषधि प्रशासन विभाग बीती शाम मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्यवाही की गयी। इस दौरान मेडिकल स्टोर में नशीले इंजेक्शन व दवाईयां बरामद होने पर मेडिकल स्टोर सीज करते हुए उनके संचालकों पर वैधानिक कार्यवाही की गयी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसटीएफ अजय सिंह के निर्देशन में एसटीएफ की कुमाऊँ यूनिट एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जनपद नैनीताल के मुखानी रोड स्थित जय श्री श्याम मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर से व्यवसायिक मात्रा में नशीले इंजेक्शन एवं नशे में प्रयोग की जाने वाली दवाइयां बरामद की गईं। कार्यवाही के पश्चात औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा उक्त मेडिकल स्टोर को अग्रिम कार्यवाही तक सील कर दिया गया। छापेमारी के दौरान मेडिकल स्टोर संचालक कपिल सिंह पुत्र रमेश सिंह, निवासी जवाहरनगर, नगला, पंतनगर तथा मेडिकल स्टोर स्वामी राहुल वार्ष्णेय पुत्र उपकार वार्ष्णेय, निवासी सावित्री कॉलोनी, हल्द्वानी मौके पर मौजूद मिले। दोनों के खिलाफ औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी है।

कार खाई में गिरी, दो की मौत

हमारे संवाददाता

चम्पावत। सड़क दुर्घटना में एक कार के खाई में गिर जाने से दो लोगों की मौत हो गयी। सूचना मिलने पर पुलिस ने उनके शवों को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्यवाही शुरू कर दी है।

सड़क दुर्घटना का यह मामला कानाकोट-सिरतोली मार्ग का है। यहां एक कार अनियंत्रित होकर करीब 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार दो लोगों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार, कार कानाकोट से लोहाघाट की ओर जा रही थी। सिरतोली के पास अचानक कार अनियंत्रित हुई और सड़क से नीचे गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार वाहन स्वामी और चालक कमल सिंह बोहरा (58) तथा बबलू चौधरी (38) गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के दौरान वहां से गुजर रही अद्वैत आश्रम मायावती

लोहाघाट की एंबुलेंस की मदद से दोनों घायलों को उपजिला अस्पताल लोहाघाट पहुंचाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। दोनों शवों का लोहाघाट में पोस्टमार्टम कराया गया। पुलिस ने पंचायतनामा की कार्रवाई पूरी कर शव परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया शुरू कर दी।मृतकों की पहचान कानाकोट निवासी कमल सिंह बोहरा, पुत्र रघुवर सिंह और बिहार के पश्चिमी चंपारण निवासी बबलू चौधरी, पुत्र गंगा चौधरी के रूप में हुई है। कमल सिंह बोहरा खटीमा स्थित लोहियाहेड पावर हाउस में एसएसओ के पद पर कार्यरत थे। वहीं बबलू चौधरी कारपेंटर का काम करते थे। स्थानीय लोगों के अनुसार, दोनों लोहाघाट में सामान खरीदने के लिए जा रहे थे।

पटेलनगर में फायरिंग मामले में पुलिस की नाकेबंदी, गिरफ्तारी सिर्फ एक!

संवाददाता

देहरादून। पटेलनगर क्षेत्र में दो गुटों में मारपीट फायरिंग की घटना के बाद पुलिस का दावा कि शहर में नाकेबंदी कर दी लेकिन इसके बावजूद मात्र एक की ही गिरफ्तारी हो पायी है। इसके अलावा पुलिस हवा में ही हाथ पैर मारने के लिए मजबूर है।

उल्लेखनीय है कि गत दिवस पटेलनगर मे दोपहर के समय साहिल, सुजल, अंशुल, आदित्य व विशाल पटेलनगर में खडे थे। इसी दौरान हरियाणा नम्बर की स्विफ्ट कार से गुरमीत नाम का युवक कुछ अन्य युवकों के साथ वहां आया। दोनों गुटों के बीच पहले से ही किसी बात को लेकर विवाद चल रहा था। उसी पर यहां पर दोनों गुटों में बहस होने लगी तभी दूसरे गुट के छह-सात युवक आगे बढे और डंडे से कार का शीशा तोड दिया। इसके बाद कार सवार युवकों ने चार-पांच राउंड फायर कर दिये और लालपुल की ओर निकल भागे। दो पहिया वाहनो से दूसरे गुट के युवकों ने उनका पीछा किया। सेंट ज्यूड्स चौक के पास खुद को घिरा देखकर गुरमीत ने सीधे गोली चला दी। गोली साहिल के कंधे में लगी और वह वहीं गिर गया। गोली चलने से वहां पर अफरा तफरी मच गयी। साहिल को दोस्तों ने महंत इन्द्रेश हास्पिटल में भर्ती कराया। घटना में इस्तेमाल की गयी कार का नम्बर एचआर 51 है। प्रारंम्भिक जांच

में सामने आया है कि दोनों पक्षों के युवक पहले एक दूसरे के मित्र रहे हैं। पिछले कुछ समय से गुरमीत का आदित्य, अंशुल व सुजल से विवाद चल रहा था। घटना का पता चलते ही पुलिस मौके पर पहुंची ओर घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला गया। जिसके बाद पुलिस ने नया गांव के पास से घटना में शामिल रोहित निवासी बडगांव सहारनपुर को गिरफ्तार कर लिया। रोहित सुभारती कॉलेज में होटल मैनेजमेंट का छात्र है। घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस सिर्फ नाकेबंदी करती रह गयी लेकिन अभी तक अन्य किसी की गिरफ्तारी में पुलिस को कामयाबी नहीं मिल सकी है। पुलिस का दावा है कि घटना के बाद से ही शहर की नाकेबंदी कर दी गयी थी। लेकिन गिरफ्तारी मात्र एक ही हो पायी है।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।